

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन
पीठासीन अधिकारी-श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या- 34/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/59

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नावां जिला डीडवाना-कुचामन।		1. अर्जुन राम पुत्र पुसा राम जाति खटीक निवासी खटीक मौहल्ला मीठड़ी तहसील नावां जिला डीडवाना-कुचामन। 2. प्रेम देवी पत्नी अर्जुन राम जाति खटीक निवासी खटीक मौहल्ला मीठड़ी तहसील नावां जिला डीडवाना-कुचामन।

दावा अन्तर्गत भु-राजस्व अधिनियम के तहत बने नियम 14(4) कृषि
प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थित:-

1. प्रार्थी की ओर से श्री रामरतन रेगर नायब तहसीलदार नावां
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री मो. शरीफ शेरानी

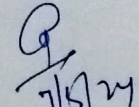
आदेश

दिनांक: 07.05.2024

प्रार्थी तहसीलदार नावां ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) के तहत पेश कर
निवेदन किया कि:-

1. मौजा ग्राम मीठड़ी के साबिक खसरा नम्बर 1327 रकबा 0.07 हैक्टर भूमि
अप्रार्थी अर्जुन राम पुत्र पुसा राम, प्रेम देवी पत्नी अर्जुन राम जाति खटिक
निवासी मीठड़ी को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि उपखण्ड अधिकारी नावां के आदेश
क्रमांक/राजस्व/02/दिनांक 27.06.2002 के द्वारा आवंटन की जाकर अप्रार्थी
अर्जुन राम पुत्र पुसा राम, प्रेम देवी पत्नी अर्जुन राम जाति खटिक निवासी
मीठड़ी को राजस्व रिकार्ड में गैर-खातेदार दर्ज किया गया था। अप्रार्थी को
उक्त भूमि आवंटन आदेश दिनांक 27.06.2002 से मूल आदेश एवं रेकार्ड
बार-बार तलाशी ली गई परन्तु उक्त आदेश एवं रेकार्ड नहीं मिलने पर आदेश
क्रमांक भू. अ./2021/4075 दिनांक 10.08.2021 के द्वारा कार्मिक की टीम
का गठन कर उक्त आदेश एवं रेकार्ड की तलाश करवाई गई परन्तु उक्त
आदेश एवं रेकार्ड बावजूद तलाशी से भी मिलना नहीं पाया गया और अब उक्त
आदेश एवं रेकार्ड मिलने की कोई सम्भावना नहीं है। अप्रार्थी अर्जुन राम पुत्र
पुसा राम, प्रेम देवी पत्नी अर्जुन राम जाति खटिक निवासी मीठड़ी को ना. सं.




जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन

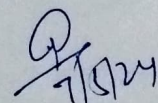
- 751 दिनांक 15.03.2005 के द्वारा गैर खातेदार दर्ज किया गया था। जिसमें अर्जुन राम पुत्र पुसा राम, प्रेम देवी पत्नी अर्जुन राम जाति खटिक निवासी मीठड़ी आज दिन तक गैर खातेदार चले आ रहे हैं।
2. यह है कि अप्रार्थी को उक्त भूमि आदेश दिनांक 27.06.2002 से आवंटित हुई थी तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अनुसार अप्रार्थी द्वारा प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू-भाग को व द्वितीय वर्ष शेष 50 प्रतिशत भू-भाग को जोतना आवश्यक था और अप्रार्थी ने उक्त नियम 14(3) की शर्त की पालना नहीं की है, जो खसरा गिरदवारी संवत् 2062 से 2077 तक की नकलों से सुस्पष्ट है।
 3. अप्रार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है तथा मौके पर भूमि बंजर है। जिस पर काश्त करना मुमकिन नहीं है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है।
 4. अप्रार्थी का विवरण जो इस प्रार्थना-पत्र में दिया गया है वह सभी जीवीत एवं व्यस्क पता जो अंकित किया गया है उसी पर अप्रार्थी निवास कर रहे हैं। उक्त सम्बन्ध में पटवारी हल्का का प्रमाण पत्र सलंगन है।
 5. अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) की पालना नहीं की है।

अतः खतौनी नकल, नामान्तरकरण, सम्पूर्ण गिरदावरी की प्रमाणित नकले व उपर्युक्तानुसार पटवारी की मौका रिपोर्ट व पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंगन कर निवेदन है कि अप्रार्थी को किये गये आवंटन दिनांक 27.06.2002 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से वकील श्री शरीफ शेरानी ने वकालतनामा पेश किया अप्रार्थी की ओर से वकील श्री शरीफ शेरानी ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि:-

1. प्रार्थना-पत्र के पैरा सं0 2 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है कि अप्रार्थी को उक्त भूमि आदेश दिनांक 27.06.2002 से आवंटित हुई थी तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अनुसार अप्रार्थी द्वारा प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू-भाग को व द्वितीय वर्ष शेष 50 प्रतिशत भू-भाग को जोतना आवश्यक था, जो जोता गया है तथा अप्रार्थी ने उक्त नियम 14(3) की शर्तों की पालना बराबर की गई है। पटवारी वगैराह बिना मौके पर जाकर ही अपने मन से गिरदावरी करते हैं, जो चलने योग्य नहीं है।
2. प्रार्थना-पत्र के पैरा सं0 3 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी का आज भी उक्त भूमि पर कब्जा निरन्तर चला आ रहा है, लास्ट की सालों में 1-2 साल काश्त नहीं करने से भूमि बंजर लग रही है। दो साल काश्त नहीं करने से अप्रार्थी के अधिकार समाप्त नहीं होते हैं।




जिला कलक्टर
जिडवाना-कुचामन

3. प्रार्थना-पत्र के पैरा सं० 4 में अप्रार्थी जीवित व व्यस्क है एवं पता जो अंकित किया गया है, उसी पर निवास कर रहे है, सही है।

:-विशेष कथन:-

1. एक बार खातेदारी प्राप्त होने के बाद खातेदारी अधिकारों को नियम 14(4) के अन्तर्गत निरस्त नहीं किया जा सकता। किसी की खातेदारी की भूमि को काशत नहीं करने व लगान अदा नहीं करने के आधार पर खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते। आवंटित भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि अप्रार्थीगण के पास नहीं है। अप्रार्थीगण आवंटन के समय भूमिहिन काशतकार थे।
2. आवंटन के 10 साल के भीतर ही न्यायलय द्वारा आवंटन रद्द किया जा सकता था, नियम 14(4) के समय सीमा लागू होती है। आवंटन के 20 साल बाद आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। कानून की यह कभी भी मंशा नहीं रही है कि अनिश्चित काल तक आवंटन को निरस्त किया जा सकता है। अप्रार्थीगण द्वारा कपट से अथवा मिथ्या व्यपदेशन से आवंटन नहीं करवाया था, आवंटन सम्पूर्ण कानून विहित प्रक्रिया अपना कर किया गया था। अप्रार्थी पर ऐसा कोई आरोप भी नहीं है कि आवंटन कपट पूर्वक व मिथ्या पूर्ण तथ्यों के आधार पर आवंटित कराया गया हो तथा निरस्त कराने पर विचार किया जा सकता है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र मय कोष्ट खारिज फरमाया जावें।

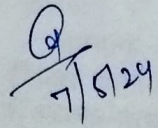
बहस के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर आराजी नं० 1327 रकबा 0.0700 हैक्टर अप्रार्थी अर्जुनलाल पुत्र पुसाराम व प्रेमदेवी पत्नी अर्जुनलाल को राज० कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत कृषि कार्य हेतु भूमि आवंटित की गई थी।

जमाबंदी ग्राम मीठडी सम्वत् 2074-77 अनुसार खसरा नम्बर 1327 रकबा 0.0700 हैक्टर किरम जमीन बा.3 अप्रार्थी अर्जुनलाल पुत्र पुसाराम व प्रेमदेवी पत्नी अर्जुनलाल हिस्सा 1/2 सा० देह के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज है।

पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम मीठडी के खसरा सं० 1327 रकबा 0.0700 हैक्टर किरम बारानी-3 गैर खातेदार अर्जुनलाल पुत्र पुसाराम व प्रेमदेवी पत्नी अर्जुनलाल हिस्सा 1/2 आज दिनांक तक काबिज नहीं है। मौके पर यह भूमि बंजर है। गैर खातेदार ने आज तक मौके पर कब्जा नहीं किया है।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सं. 2062-77 एवं मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार आवंटी/अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तोंनुसार मौके पर कब्जा काशत नहीं किया गया है।




जिला कलक्टर
जयपुर-कुचामन

अप्रार्थी का आराजी भूमि पर कभी कब्जा काशत रहा हो ऐसा कोई दस्तावेजी आधार/नकल गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे भी उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कभी भी कब्जा काशत नहीं होने के तथ्य की पुष्टि होती है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने विशेष कथन के रूप में यह तर्क दिया कि खातेदारी अधिकार प्राप्त हो के पश्चात इन अधिकारों को नियम 14(4) के तहत समाप्त नहीं किया जा सकता एवं साथ ही यह भी तर्क दिया कि नियम 14(4) के तहत आवंटन 10 साल तक ही खारीज किया जा सकता है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने उक्त दोनों कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2011(2)DNJ Raj-1 709, RRT 2008(1) RRT 610 प्रस्तुत किये। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अन्य कोई नियम प्रस्तुत नहीं किया।

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (एलोटमेन्ट लैण्ड) 1970 के नियम 04 के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने पर जिला कलक्टर द्वारा आवंटन को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। उक्त नियमों के नियम 14(3) के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि आवंटी को भूमि पर काशत करनी होगी। उक्त नियमों के नियम 14(8)A के तहत भी यदि भूमि को निर्धारित अवधि में काशत नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार में पुनः पुर्नगठित करने के प्रावधान है।

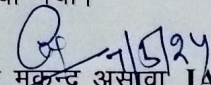
अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात नियम 14(4) के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकने का तर्क दिया है परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में अप्रार्थी का स्टेट्स गैर खातेदारी अधिकार का ही है।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दानों न्यायिक दृष्टांत में प्रथम नियमन को चुनोती देने से संबंधित है एवं द्वितीय में काशत किये जाने बाबत 02 वर्ष अवधि की गणना किस प्रकार की जावेगी इससे संबंधित है। दोनों दृष्टांत इस पर लागू नहीं होते हैं। क्योंकि आवंटन के 22 वर्ष पश्चात भी आवंटित भूमि पर न तो अप्रार्थी द्वारा काशत की गई न ही अप्रार्थी का कब्जा है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के उप नियम 14(4) के तहत अप्रार्थी अर्जुनलाल पुत्र पुसाराम व प्रेमदेवी पत्नी अर्जुनलाल हिस्सा 1/2 को किया गया आवंटन निरस्त करने बाबत प्रार्थी तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा मीठडी के खसरा नम्बर 1327 रकबा 0.0700 हैक्टर पर आवंटी/अप्रार्थी की दर्ज गैर खातेदारी/आवंटन को निरस्त किया जाकर उक्त भूमि पुनः राजकीय सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार, नावां को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की जावे।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 07.05.2024 को सुनाया गया।




(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन